

सम्पादकीय

ज्ञानवापी मामले में मुरिलम समाज को गलती सुधारने की पहल करनी चाहिए

सत्ता लाभ आर चुनाव म परजय क भय स पांडित इन लागा का राष्ट्रीय अस्मिता की अवमानना करने और उसे नकारने में लाज ही नहीं आती। लोभ, भय और मौन हो जाने का परिणाम भारत का राष्ट्रीय समाज 75 वर्ष पूर्व भुगत चुका है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा वाराणसी के प्रसिद्ध विश्वनाथ मंदिर से सटी ज्ञानवापी मस्जिद में हुए सर्वेक्षण से उस दावे की पुष्टि हो गई है कि वह हिन्दू मंदिर पर ही बनाई गई थी। इस सर्वेक्षण को रोकने के लिए मुस्लिम पश्च द्वारा न्यायालय में चरम सीमा तक जाकर तरक्कि दिए गए। वहाँ बीती 31 जनवरी को वाराणसी की एक न्यायालय ने हिंदू पक्ष को ज्ञानवापी मस्जिद के व्यास जी तलगृह में पूजा का अधिकार दे दिया है। पूर्ण विधि विधान पूजा अर्चना शुरू हो गई है। हिंदू पक्ष कुछ समय से ज्ञानवापी परिसर में स्थित एक तलगृह में पूजा का अधिकार मांग रहा था। यह तलगृह मस्जिद परिसर में है। वर्ष 1992 तक व्यास जी तलगृह में पूजा नियमित तौर पर होती थी। 6 दिसंबर 1992 को हुए बाबरी मस्जिद विघ्नांस के बाद 1993 से व्यासजी के तलगृह बद कर दिया गया और बैरिकेडिंग कर दी गई। उस समय समाजवादी पार्टी की सरकार थी और मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री थे। अयोध्या राम जन्मभूमि मामले को लेकर मुलायम सिंह यादव ने बैरिकेडिंग लगा दी कि यहाँ साप्रदायिक माहौल ना बिछे और लड़ाई-झगड़े ना हों। पहले बांस-बल्ली लगाकर टेंरेरी तौर पर बैरिकेडिंग की गई और बाद में पक्की तरह से बंद कर दिया गया। इसके बाद यहाँ पर वार्षिक तौर पर माता श्रींगार गैरी की पूजा हो रही थी। ज्ञानवापी में किए गए सर्वेक्षण की जो रिपोर्ट न्यायालय में प्रस्तुत हुई, उसके आधार पर कोई भी कह सकत है कि वह मंदिर ही है। मुस्लिम पक्ष को इसका जान काफी पहले से था। इसलिए उन वस्तुओं को छिपा दिया गया था और ढक दिया गया था जो हिन्दू धर्म के प्रतीक और विहृत हैं। सबसे बड़ी बात शिवलिंग का मिलना है। पौराणिक ग्रंथों से पता चलता है कि ज्ञानवापी कुएं का निर्माण स्वयं भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से किया था। पौराणिक काल से ही काशी विश्वनाथ कॉरिडोर

का इलाका अविमुक्त क्षेत्र के नाम से प्रसिद्ध रहा है। महाभारत में भी काशी विश्वनाथ कौमुदीर के पूरों क्षेत्र को अविमुक्त क्षेत्र के नाम से पुकारा गया है। वर्तमान में स्थित ज्ञानवापी मस्जिद भी अविमुक्त क्षेत्र का ही भाग रहा है। इस क्षेत्र में स्थित ज्ञानवापी मस्जिद को मुक्त कराने के लिए सैकड़ों वर्षों से विश्व भर के हिंदू संघर्ष कर रहे हैं। होना तो यह चाहिए था कि स्वतंत्रता के बाद केंद्र सरकार मुगल काल में हिन्दू धर्मस्थलों को तोड़कर या उन्हीं ढांचों पर खड़ी की गई मस्जिदों को हिंदुओं को सौंपने की नीति बनाती। लेकिन कांग्रेस सहित अन्य पार्टियां मुसलमानों की नारजगी से बचने के लिए हिंदुओं के वैध दावों को ठुकराती रहीं। मथुरा और वाराणसी में हिंदुओं के सर्वोच्च आराध्यों के पवित्र मंदिर के बगल में बनी मस्जिद के हिन्दू मंदिर होने की बात पहिले नहरू से लेकर तमाम नेताओं को ज्ञात थी। लेकिन उन्होंने इस दिशा में सोचने का कष्ट इसलिए नहीं उठाया क्योंकि वे हिंदुओं की सहनशक्ति को जानते थे। वरना क्या कारण था कि हिंदुओं की विवाह व्यवस्था संबंधी रीत-स्थितियों को तो उलट-पलट दिया गया किंतु मुस्लिम पर्सनल लॉ को छेड़ने की हिम्मत नहीं हुई। देश का बटवारा धर्म के नाम पर हमारे नेताओं ने स्वीकार किया था। सर्व धर्म समभाव के भारतीय संस्कारों के कारण भले ही मुस्लिमों की बड़ी आबादी भारत में रह गई और पाकिस्तान के उलट भारत ने अपने को धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनाया किंतु ये भी उतना ही सही है कि तत्कालीन शासकों ने मुस्लिम तुषीकरण के फेर में बहुसंख्यकों की धार्मिक भावनाओं को धक्का पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। यदि सरदार पटेल न होते तब बड़ी बात नहीं सोमनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार भी न हो पाता। अयोध्या का विवाद तो स्वाधीनता के पहले से चला आ रहा था। वास्तव में, देश में एक ऐसी जमात है जो भय और लोभ से भरी हुई है। उसमें कायरता की कीचड़ है। वह ऐतिहासिक यथर्थ और सांस्कृतिक सत्य का सामना करने से कतराती है। समस्या का समाधान सौदेबाजी में तलाशी है और समस्या को टालते जाने को अपनी कुशलता और चतुरुई मानती है। इस जमात के भगीरथ हैं राजनेता। ऐसा राजनेता जिनकी सोच और दृष्टि का क्षितिज केवल एक चुनाव से दूसरे चुनाव तक का है। भावी पीढ़ियों, दरशाविद्यों और शताविद्यों की बात सोचने का सार्थक उनमें नहीं है। वे हम मर गए तो किसने दुनिया देखी की मानसिकता से पीड़ित हैं। सत्ता लोभ और चुनाव में परायज के भय से पीड़ित इन लोगों का राष्ट्रीय अस्मिता की अवमानना करने और उसे नकारने में लाज ही नहीं आती। लोभ, भय और मौन हो जाने का परिणाम भारत का राष्ट्रीय समाज 75 वर्ष पूर्व भूत जन्मा है। गजाननीविक नेतृत्व के ल्योग भय और शयोगी समाज के ऐसे

मुक्ता हा राजनीतिक नगृप के लागे जा नये देव राष्ट्रपति सभाजंक के मान में से तुष्टिकरण और खुशामद कर जन्म हुआ था। यह इतिहास सिद्ध अनुभव है कि हिन्दुओं का मौन राष्ट्र के विभाजन को जन्म देता है। अल्पसंख्यकों की मुखरता और उनका तुष्टिकरण राष्ट्र के भूगोल को बिगाड़ा और इतिहास का मान भंग करता है। 1991 में केंद्र की नरसिंहा राव सरकार ने जो कानून बनाया उसके अनुसार 15 अगस्त 1947 को किसी भी धर्मस्थल की जो स्थिति थी उसे परिवर्तित नहीं किया जाएगा। लेकिन अयोध्या विवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने अपना निर्णय इस आधार पर दिया कि बाबरी ढांचा हिन्दुओं के मंदिर को मस्जिद का रूप देकर खड़ा किया गया था। ठीक वही बात ज्ञानवापी के बारे में भी सामने आ रही है। अयोध्या विवाद को सुलझाकर सर्वोच्च न्यायालय ने जो रास्ता खोल दिया वह उन सभी धर्मस्थलों को मुक्त करवाने में सहायक होगा जिनको मुस्लिम शासकों ने बलपूर्वक मस्जिद का रूप दे दिया। मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि के बारे में भी ऐसा ही दावा है। ये सब देखते हुए मुस्लिम धर्मगुरुओं को अपने समुदाय के लोगों को समझाना चाहिए कि वे हठधर्मिता के बजाय समझदारी और व्यवहारिकता से काम लें। इसमें दो राय नहीं है कि मुगलों द्वारा पूरे देश में हिन्दुओं के धर्मस्थलों को नष्ट करने का काम बड़े पैमाने पर हुआ। प्राचीन धर्म स्थलों के बारे में जो तथ्य उभरकर सामने आ रहे हैं वे चौंकाने वाले हैं। ज्ञानवापी में हिन्दू पक्ष को पूजा का अधिकार प्रदान करने के न्यायालय के निर्णय के बाद मुस्लिम पक्ष ने इस पर नाराजगी जताई है। मुस्लिम पक्ष ने कहा है कि फैसले के बाद हाईकोर्ट में इस ओदेश के खिलाफ अपील की जाएगी। मुस्लिम पक्ष ने इस फैसले को भी नकार दिया है। इससे पहले मुस्लिम पक्ष ने एसएसई के सर्वे को भी नकार दिया था। ज्ञानवापी परिसर में स्थित माता श्रींगार गौरी भी पूजा का अधिकार मांगा जा रहा है। देखा जाए तो, मुस्लिम पक्ष द्वारा इस बारे में वही गलती दोहराई जा रही है जो अयोध्या विवाद में देखने मिली। इसलिए इस विवाद को निपटाने के लिए अदालत ही एकमात्र विकल्प बचता है, जहां ठोस प्रमाणों के आधार पर निर्णय होते हैं। अयोध्या में हिन्दू मंदिर होने की बात भी वहां की गए उत्थनन से ही तय हुई। वही प्रक्रिया ज्ञानवापी के बारे में भी अपनाई जा रही है। मुस्लिम समाज को ये बात समझ लेनी चाहिए कि जिन राजनीतिक दलों के बहकावे में आकर वह सच्चाई की स्वीकार करने से बचत है उनका उद्देश्य मात्र उनके बोत प्राप्त करना है। जहां मूर्ति हो और जिस भूमि पर जबरन कब्जा किया गया हो, वहां मस्जिद बनाने और नमाज पढ़ने को कुरान और पैगम्बर दोनों ने मना किया है। मस्जिद को हटाने का भी कुरान में निषेध नहीं है। ऐसे में वो विशाल हृदय का प्रदर्शन करते हुए अतीत में मुगल शासकों द्वारा हिन्दुओं के धर्मस्थलों पर बलपूर्वक अधिकार जमाने और नियंत्रण किए जाने वाली गलती को सुधारने की पहल करते हुए उनकी सद्बावना प्राप्त करें। सद्बावना और सहिष्णुता एकपक्षीय नहीं, द्विपक्षीय होती है। एक पक्ष को अपमानित करके दूसरे पक्ष को सम्मान देने से सद्बाव को नहीं, शत्रुता का जन्म होता है। जन-जन को दिग्ध्रमित करने की राजनीति दलाली के दुष्क्र की लंबी कहानी है।

मोदी के 'चार सौ पार' के दावे में गुंथे सियासी प्रबंधन के तार..!

अब सवाल यह है कि क्या भाजपा को लोकसभा चुनाव में इसका लाभ बोटों के रूप में मिलेगा, इसका जवाब पाने के लिए हमें नीतियों का इंतजार करना होगा। इसके दो कारण हैं। पहला तो यह कि भारत रत्न पुरस्कारों में निहित राजनीतिक महत्वाकांक्षा पूर्ववर्ती अनुभवों में बहुत ज्यादा फलित होती नहीं दिखती है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने राष्ट्रपति के अधिपायषण पर चर्चा के उत्तर में संसद में आगामी लोकसभा चुनाव में भाजपा द्वारा अपने दम पर 370 और एनडीए द्वारा 4 सौ के पार सीटें जीतने का जो दावा किया गया था, उसका आधार मोदी सरकार द्वारा भारत रत्न सम्मानों की झड़ी तथा विपक्षी तथा दूसरे दलों को अपनी छतरी में लाने के अभियान से समझा जा सकता है। वैसे प्रधानमंत्री ने जो दावा कर रहे हैं, वह जमीन पर कितना उत्तराधारी, यह तो चुनाव नीति ही बताएँ, लेकिन उसे साकार करने की दिशा में स्वयं प्रधानमंत्री और उनकी पार्टी भाजपा जिस तरह जमीन आसमान एक किए दे रही है, उससे लगता है कि यह सच हो भी सकता है। भले ही चुनाव पूर्व किए जा रहे ओपीनियन पोल के नीति अभी इस दावे को दूर की कौड़ी ही बता रहे हों। बहरहाल, भाजपा की चार सौ पार की यह रणनीति कई स्तरों पर नजर आती है और साम-दाम-दंड-भेद से प्रेरित है। नैतिक आधार पर इसकी आलोचना हो सकती है, लेकिन व्यावहारिक स्तर पर वह सफल होती दिखती है। यूं भी राजनीति मूलतः सत्ता का रूप है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के कन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह बखूबी समझते हैं। इसीलिए कदम आगे बढ़ने के लिए एक पीछे हटने में भी उन्हें गुरेज नहीं। आज क्या हासिल होगा, यही प्राथमिक लक्ष्य है। कल क्या भावी इतिहास इसका आकलन रूप में करेगा, नीति शास्त्र कहां जगह मिलेगी, नियम-मानकों की लक्ष्मण रेखाओं की सुविधा व्याख्या कैसे की जाएगी, लोकतंत्र की आधारभूत संस्थाएँ हाथ किसे सेल्यूट कर रहे हैं सवाल आगे भी उठेंगे लेकिन राजनीति शास्त्र में इन सवालों की चिंता किए बगैर बहुतांशं जनाकांक्षा को किस भाव से पढ़ा और उसे किस तरह अपने नोडों जाए, यह हिकमत है। पॉलिटिकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। और मोदी प्रैदेंगिकी के मास्टर हैं। बाजीगरी को इस साल घोषित भारत रत्नों में बूझने की कोशिश के आलोचक कर रहे हैं। हाल भारत रत्न जैसा सर्वोच्च पुरुष जाति, धर्म, समृद्धय और दुराग्रहों से परे है और देश असाधारण सेवा के लिए दिया गया है। लेकिन इस बार दिए गए भारत रत्नों में जाति और धौम-धर्म के महीन समीकरण साधारण भाव भी निहित है। भले ही तौर पर यहा कहा जाए कि

पर्यावरण-हिमालय में कम

इस बार पहाड़ों पर बर्फ न गिरने से हिमालयी राज्यों समेत देश भर में संकट खड़ा हो गया है। इसके लिए हमें स्थानीय मूल कारकों पर ध्यान देना होगा। क्या हिमालय की गोद में बसे भारत के कई राज्य, नेपाल और पाकिस्तान के गिलगित-बाल्टिस्तान क्षेत्र में देर से हुई बर्फबारी महज एक असामान्य घटना है या फिर जलवायु परिवर्तन के प्रभावों का संकेत? यह बात गैर करने की है कि बीते कुछ वर्षों में हिमालय लगातार असामान्य और चरम मौसम की चेपेट में है, और इस बार बरसात ने हिमाचल प्रदेश से लेकर उत्तराखण्ड तक जबर्दस्त कहर ढाया था। लेकिन इस बार लगातार 45 दिन तक पहाड़ों पर बर्फ न गिरने से हिमालयी राज्य ही नहीं, शेष भारत के लिए भी संकट खड़ा हो गया है। जान लें, देर से हुई बर्फबारी से राहत तो है, पर इससे उपजे खतरे भी हैं। कश्मीर के बाशिंदों के लिए जीवकोपार्जन का मूल आधार है-जाड़े का मौसम। यहां जाड़े के कुल 70 दिन गिने जाते हैं। सतर दिन की बर्फबारी 15 दिन में सिमटने से दिसंबर और जनवरी में हुई लगभग 80-

किसानों के मसीहा प्रधा

चौधरी चरण सिंह के सियासत में प्रवेश की बात की जाये तो चरण सिंह सबसे पहले 1937 में छपरौली से उत्तर प्रदेश विधानसभा के लिए चुने गए एवं 1946, 1952, 1962 एवं 1967 में विधानसभा में अपने निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। पूर्व प्रधानमंत्री और किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह, पूर्व पीएम नरसिंहराव और कृषि वैज्ञानिक एमएस स्वामीनाथन को भारत रत्न की घोषणा में चौधरी चरण सिंह के बारे में यह जरूर कहा जा सकता है कि यह सम्मान उन्हें काफी पहले मिल जाना चाहिए था। चौधरी चरण सिंह का सम्मान देर से लिया गया एक फैसला है। चौधरी चरण सिंह ‘भारत रत्न’ के लिये पूरी तरह से योग्य थे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के नूरपुर में चरण सिंह का जन्म 23 दिसंबर 1903 को एक ग्रामीण किसान परिवार में हुआ था। एक मध्यम वर्गीय जाट किसान परिवार में जन्मे चौधरी चरण सिंह लोकतंत्र के बड़े पैरोकार थे। चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न से सम्मानित करने में इतना समय क्यों लगा यह यक्ष प्रश्न हो सकता है। अब जबकि केन्द्र की नरेन्द्र मोदी सरकार ने चौधरी चरण सिंह को वह सम्मान दिलाया है जिसके वह हकदार थे तो इस पर किसी को एतराज नहीं होगा। उन्होंने 1923 में विज्ञान से स्नातक किया एवं 1925 में आगरा विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त चौधरी चरण सिंह ने गाजियाबाद से एक अधिकारी के रूप में पेश की शुरूआत की थी। चरण सिंह 1929 में मेरठ आ गये और बाद में काग्रेस में शामिल हो गए। चौधरी चरण

वैचारिक मतभेदों के परे जाकर भारत रत्न पुरस्कार दिए थे। लेकिन न साधकर भी बहुत कुछ साधने की सियासी कारिगरी इसमें साफ़ झलकती है। अब सबाल यह है कि क्या भाजपा को लोकसभा चुनाव में इसका लाभ बोटों के रूप में मिलेगा, इसका जवाब पाने के लिए हमें नतीजों का इंतजार करना होगा। इसके दो कारण हैं। पहला तो यह कि भारत रत्न पुरस्कारों में निहित राजनीतिक महत्वाकांक्षा पूर्ववर्ती अनुभवों में बहुत ज्यादा फलित होती नहीं दिखी है। इसका कारण शायद यह भी है कि पहले के कर्णधारों ने भारत रत्नों के जरिए राजनीतिक हित साधने की ज़ीनी कोशिश जरूर की थी, लेकिन वह उनीं शिद्दत से नहीं थी, जैसी कि इस बार दिखती है। दूसरे, जो पुरस्कार दिए गए हैं या और भी दिए जा सकते हैं, वो ठीक चुनाव के मुहाने पर हैं। लिहाजा इसका कुछ न कुछ असर होने की पूरी संभावना है, जिसका फायदा भाजपा और एनडीए को किसी न किसी रूप में होगा। तीसरे, विचार और आग्रहों के स्तर पर जैसी जबर्दस्त गोलबंदी ऊपर से नीचे तक अब दिखाइ दे रही है या करने की कोशिश की जा रही है, वैसी एक दशक पहले तक नहीं थी। जिस होशियारी से ये भारत रत्न दिए गए हैं, उसकी आलोचना मोदी विरोधी भी खुलकर नहीं कर पा रहे हैं। हालांकि इसमें खतरा यह है कि अगर यह दांव चल गया तो आने वाले समय में किसी भी प्रधानमंत्री को 'भारत रत्न लो और बोट दो' की काम करना होगा। इसमें हो भी चुकी है। मायावत के नेता कांशीराम और बाला साहब ठाकरे को की मांग कर दी है। इन घोषणा हो भी सकती है एनडीए के शामियाने राजनीतिक स्टॉल लगाकर शब्दों में कहें तो अब फ़िक्षेत्र में अन्यतम योगदान देश सेवा के लिए भारत राष्ट्रीय कृतज्ञता जताने का चुका है। यह असंभव नहीं रत्न अब जातीय/सामुदायिक क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व राजनीतिक लाभबंदी का आधार पर ही दिए जाने वाले नहीं कि लोकसभा चार सौ पार का आंदोलन करने के लिए भाजपा अनुबंध कुनबा बढ़ाने की हर संभावना कर रही है। पहले जदयूत अब रालोद का एनडीए होना, पंजाब में अकाल लौटाने की कवायद इसकी है। उत्तर दक्षिण में पी.वी.को भारत रत्न देने का सत्तारूढ़ रही भारत राष्ट्रीय अध्यक्ष केसीआर ने अपना निर्वाह खेती और पशुधन पालन से करते हैं। लगभग बर्फ़ रहते या देर से सर्दी का प्रभाव उन लोगों के लिए विनाशकारी हो सकता है। पूरे हिमालयी क्षेत्र में कम बर्फ़बारी

ते पर ही शुरूआत ने दलितों के बाद कांग्रेस यह कह रही है कि उन्हें प्रधानमंत्री तो हमने ही बनाया था। पी.वी.नरसिंहराव अविभाजित आंध्र के मुख्यमंत्री थे। ऐसे में आंध्र में भी इसका कुछ तो संदेश गया ही है। खासकर तब कि जब भाजपा और चंद्रबाबू नायडू की नीटीपी फिर साथ आने की बात चल रही है। इसी तरह वर्तमान संदर्भों में महान कृषि वैज्ञानिक एम.एस. स्वामीनाथन को भारत रव देना विज्ञान प्रतिभा के सम्मान से ज्यादा तमिलनाडु की जनता को राजनीतिक संदेश देना ज्यादा है। हालांकि वहाँ की द्रविड़ राजनीति में अभी भी भाजपा के लिए कोई खास जगह नहीं है, लेकिन यह रेत में घरेंदा बनाने की कोशिश जरूर है। एक बात साफ है कि भाजपा चुनाव जीतने के लिए केवल राम लहर, हिंदुत्व और सुनहरे अर्थिक सपनों के भरोसे नहीं है। वह इसी के समानांतर गरीब कल्याण, रेवड़ी कल्वर, सियासी गोलबंदी, धार्मिक ध्वनीकरण, मोदी के वैश्विक नेता बनाने, भारत के विश्व गुरु होने की दिशा में आगे कूच करने तथा युवाओं का सपना सच होने के दावों के टूल्स का भी भरपूर उपयोग कर रही है। इस शोर में गरीबी, बेरोजगारी, अर्थिक विकास में छिपी विषमता, जातीय और साम्प्रदायिक तनाव जैसे मुद्रे तूती की आवाज बनकर रह जाते हैं। इसमें दो राय नहीं कि बीते एक दशक में भाजपा ने यह समिति कर दिया है कि चुनाव रही थी। को भारत और नीटी थी। और उसका कोई सानी नहीं है। और उस पर राजनीतिक बढ़त हासिल करनी है तो विरोधी दलों को अब भी नए उपकरण, नए तरीके और जुगले अपनाने होंगे। भाजपा को भाजपा के पिच पर नहीं हराया जा सकता। प्रधानमंत्री के दबे में एक पेंच भाजपा द्वारा 370 सीटें अपने दम पर जीतने का है। यह आंकड़ा कहाँ से और कैसे आया? यह केवल शोशेबाजी है या फिर इसके पीछे भी कोई रणनीति है? यह सबाल इसलिए भी मौजूद है क्योंकि हाल में हुए ओपनियन पैल भाजपा और एनडीए को तीसरी बार सत्ता तो दिला रहे हैं, लेकिन भाजपा की सीटों में बेहत मामूली इजाफा दिखा रहे हैं। 2019 में भाजपा ने अकेले 303 सीटें जीती थीं। यानी 370 तक पहुंचने के लिए उसे 67 सीटें और चाहिए। ये कहाँ से आएंगी? जिन राज्यों में भाजपा एक या दो नंबर पर है, वहाँ वह अधिकतम सीटें पहले ही जीत रही है। अर्थात 67 सीटें उसे उन राज्यों में जीतनी होंगी, जहां क्षेत्रीय दल सत्ता में हैं। यह तभी संभव है, जब मोदी और रामलला की जबर्दस्त आंधी चले। ऐसा फिलहाल तो नहीं लग रहा है। लेकिन यदि ऐसा कोई अंडर करंट है तो वह नीतीजों में ही झलकेगा। संभव है कि पीएम द्वारा 370 का आंकड़ा बताने के पीछे कश्मीर से धारा 370 हटाने का संदेश निहित हो। यह जाताने की कोशिश भी हो सकती है कि हमने अपने कोर एजेंडे को पूरा कर दिया है। लिहाजा हम ही तीसरी बार भी सत्ता के दबेदार हैं।

और अनियमित बारिश से पानी और कृषि वानिकी सहित प्रतिकूल पारिस्थितिक प्रभाव पड़ने की आशंका है। अगर तापमान जल्द ही बढ़ जाता है, तो देर से होने वाली बफ्फबारी और भी अधिक त्रासद होगी। गर्मी से यदि ग्लेशियर अधिक पिघले, तो आने वाले दिनों में पहाड़ी राज्यों में स्थापित सैकड़ों में बाट की जल द्युत परियोजनाओं पर भी संकट आ रहता है। लंबे समय तक सूखे के कारण नम और अन्य नदियों का जल स्रर अभी नकारात्मक सीमा में है। देश की संपन्न धर्यवक्स्था का आधार खेती है, जो बाँध चाई के हो नहीं सकती। इसके लिए निवार्य है कि नदियों में जल-धारा विरल रहे, लेकिन नदियों में जल लाने वाली जिम्मेदारी तो उन बर्फ के पहाड़ों की जो गर्मी होने पर धीरे-धीरे पिघलकर आ जाती है। साफ है कि न वाले दिनों में केवल कश्मीर या हिमाचल, बल्कि पूरे देश में जल संकट खड़ा होगा। ऐसे में, सवाल यह उठता है कि इस अनियमित मौसम से कैसे बचा जाए? ग्लोबल वार्मिंग या अल नीनो को दोष देने से पहले हमें ऐसे स्थानीय कारकों पर विचार करना होगा, जिससे प्रकृति कूपित है। जून, 2022 में गोविंद बल्लभ पत राष्ट्रीय हिमालयी पर्यावरण संस्थान द्वारा जारी रिपोर्ट $\% \text{ एनवायरनमेंटल असेसमेंट } \text{ ऑफ } \text{ ट्रूरिज्म } \text{ इन } \text{ द } \text{ इंडियन हिमालयन } \text{ रीजन } \%$ में कड़े शब्दों में कहा गया था कि हिमालयी क्षेत्र में बढ़ते पर्यटन के चलते हिल स्टेशनों पर दबाव बढ़ रहा है। साथ ही पर्यटन के लिए जिस तरह से इस क्षेत्र में भूमि उपयोग में बदलाव आ रहा है, वह अपने-आप में एक बड़ी समस्या है। जंगलों का बढ़ता बिनाश भी इस क्षेत्र के इकोसिस्टम पर व्यापक असर डाल रहा है। इस रिपोर्ट में हिमाचल प्रदेश में पर्यटकों के वाहनों और इसके लिए बन रही सड़कों के कारण बन्यजीवों के आवास नष्ट होने और जैव विविधता पर विपरीत असर पड़ने की बात भी कही गई थी।

पर्यावरण- हिमालय में कम बर्फबारी के मायने, संकट के समाधान पर कारगर काम की जरूरत

राज्यों समेत देश भर में संकट खड़ा हो गया है। इसके लिए हमें स्थानीय मूल कारकों पर ध्यान देना होगा। क्या हिमालय की गोद में बसे भारत के कई राज्य, नेपाल और पाकिस्तान के गिलगित-बालिस्तान क्षेत्र में देर से हुई बर्फबारी महज एक असामान्य घटना है या फिर जलवायु परिवर्तन के प्रभावों का संकेत? यह बात गौर करने की है कि बोते कुछ वर्षों में हिमालय लगातार असामान्य और चरम मौसम की चपेट में है, और इस बार बरसात ने हिमाचल प्रदेश से लेकर उत्तराखण्ड तक जर्बरदस्त करह ढाया था। लेकिन इस बार लगातार 45 दिन तक पहाड़ों पर बर्फ न गिरने से हिमालयी राज्य ही नहीं, शेष भारत के लिए भी संकट खड़ा हो गया है। जान लें, देर से हुई बर्फबारी से राहत तो है, पर इससे उपजे खतरे भी हैं। कश्मीर के बाशिंदों के लिए जीवकोपार्जन का मूल आधार है-जाड़े का मौसम। यहां जाड़े के कुल 70 दिन गिने जाते हैं। सत्तर दिन की बर्फबारी 15 दिन में स्थिरने से दिसंबर और जनवरी में हुई लगभग 80-



हिंदू-कुश हिमालयी क्षेत्र में जल सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण खतरा पैदा करते हैं। यह समझना होगा कि सर्दियों में कम बर्फबारी का कारण अल नीने नहीं है। अल नीनो के कारण केवल गर्मी और मानसून की बारिश प्रभावित होती है। गौरतलब है कि पहाड़ों पर रहने वाले लोग आजीविका के लिए प्राकृतिक संसाधनों पर ही निर्भर हैं। वे अपना निर्वाह खेती और पशुधन पालन से करते हैं। लगभग बर्फ रहित या देर से सर्दी का प्रभाव उन लोगों के लिए विनाशकारी हो सकता है। पूरे हिमालयी क्षेत्र में कम बर्फबारी

री 1970 से बार वे नीतियों का सार्वजनिक रूप से विरोध किया था। हालाँकि गुटों से भरी उत्तर प्रदेश कांग्रेस में उनकी स्थिति कमज़ोर हो गई थी, लेकिन यही वह समय था जब उत्तर भारत में विभिन्न जातियों के मध्यम से किसान समूदायों ने उन्हें अपने प्रवक्ता और बाद में अपने निर्विवाद नेता के रूप में देखना शुरू कर दिया। यह भी ध्यान देने योग्य है कि उत्तर प्रदेश कांग्रेस के भीतर अपनी स्पष्ट नीतियों और मूल्यों को व्यक्त करने की उनकी क्षमता ने उन्हें अपने सहयोगियों से अलग खड़ा किया। इस अवधि के बाद, चरण सिंह 1 अप्रैल 1967 को कांग्रेस से अलग हो गए, विपक्षी दल में शामिल हो गए और यूपी के पहले गैर-कांग्रेसी मुख्यमंत्री बने। यह वह समय था जब 1967 से 1971 तक भारत में गैर-कांग्रेसी सरकारें एक मजबूत ताकत थीं। जनता गठबंधन के एक प्रमुख घटक भारतीय लोक दल के नेता के रूप में 1977 में जयप्रकाश नारायण की पसंद मोरारजी देसाई के प्रधानमंत्री बनने की उनकी महत्वाकांक्षा से उन्हें निराश हुई। 1977 के लोकसभा चुनावों के दौरान जब बिखरा हुआ विपक्ष चुनाव से कुछ महीने पहले जनता पार्टी के बैनर तले एकजुट हुआ, जिसके लिए चौधरी चरण सिंह 1974 से लगभग अकेले ही संघर्ष कर रहे थे। उस समय वह राजनारायण के प्रयासों के कारण ही प्रधानमंत्री बने। राजनारायण जनता पार्टी-सेक्युरिटी के अध्यक्ष थे और उन्होंने चरण सिंह को प्रधानमंत्री के रूप में पदोन्नत करने का आश्वासन दिया था, जिस तरह उन्होंने उर्वशी 1967 में उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बनने में मदद की थी। हालाँकि, जब इंदिरा गांधी की कांग्रेस पार्टी ने सरकार से समर्थन बापस ले लिया तो उन्होंने केवल 24 सप्ताह के कार्यकाल के बाद इस्तीफा दे दिया। चरण सिंह ने कहा कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया क्योंकि वह इंदिरा गांधी के आपातकाल से संबंधित अदालती मामलों को बापस लेने के लिए ब्लैकमेल किए जाने के लिए तैयार नहीं थे। छह महीने बाद नये चुनाव हुए। चरण सिंह 1987 में अपनी मृत्यु तक विपक्ष में लोकदल का नेतृत्व करते रहे। बातौर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में जोत अधिनियम, 1960 को लाने में भी उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। यह अधिनियम जमीन रखने की अधिकतम सीमा को कम करने के उद्देश्य से लाया गया था ताकि राज्य भर में इसे एक समान बनाया जा सके। देश में कुछ ही राजनेता ऐसे हुए हैं जिन्होंने लोगों के बीच रह कर सरलता से कार्य करते हुए इतनी लोकप्रियता हासिल की हो। एक समर्पित लोक कार्यकर्ता एवं सामाजिक न्याय में दृढ़ विश्वास रखने वाले चरण सिंह को लाखों किसानों के बीच रहकर प्राप्त आत्मविश्वास से काफी बल मिलता रहा। चौधरी चरण सिंह ने अत्यंत साधारण जीवन व्यतीत किया और अपने खाली समय में वे पढ़ने और लिखने का काम करते थे। उन्होंने कई किताबें एवं रूचार-पुस्तिकाएं लिखीं जिसमें 'जर्मीदारी उन्मूलन', 'भारत की गरीबी और उसका समाधान', 'किसानों की भूसंपत्ति या किसानों के लिए भूमि', 'प्रिवेशन ऑफ़ डिवीजन ऑफ़ होल्डिंग्स बिलो ए सर्टेन मिनिमम', 'को-ऑपरेटिव फार्मिंग एक्स-रे' आदि प्रमुख हैं।

किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देकर वाकई प्रधानमंत्री मोदी ने दिल जीत लिया

चांधरा चरण सिंह के सियासत में प्रवेश की बात की जायें तो चरण सिंह सबसे पहले 1937 में छपरौली से उत्तर प्रदेश विधानसभा के लिए चुने गए एवं 1946, 1952, 1962 एवं 1967 में विधानसभा में अपने निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। पूर्व प्रधानमंत्री और किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह, पूर्व पीएम नरसिंह राव और कृषि वैज्ञानिक एमएस स्वामीनाथन को भारत रत्न की घोषणा में चौधरी चरण सिंह के बारे में यह जरूर कहा जा सकता है कि यह सम्मान उन्हें काफी पहले मिल जाना चाहिए था। चौधरी चरण सिंह का सम्मान देर से लिया गया एक फैसला है। चौधरी चरण सिंह 'भारत रत्न' के लिये पूरी तरह से योग्य थे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के नूरपुर में चरण सिंह का जन्म 23 दिसंबर 1903 को एक ग्रामीण किसान परिवार में हुआ था। एक मध्यम वर्गीय जाट किसान परिवार में जन्मे चौधरी चरण सिंह लोकतंत्र के बड़े पैरोकार थे। चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न से सम्मानित करने में इतना समय क्यों लगा यह यक्ष प्रश्न हो सकता है। अब जबकि केन्द्र की नेरन्द मोदी सरकार ने चौधरी चरण सिंह को वह सम्मान दिलाया है जिसके वह हकदार थे तो इस पर किसी को एतराज नहीं होगा। उन्होंने 1923 में विज्ञान से स्नातक किया एवं 1925 में आगरा विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त चौधरी चरण सिंह ने गाजियाबाद से एक अधिवक्ता के रूप में पेशे की शुरुआत की थी। चरण सिंह 1929 में मेरठ आ गये और बाद में कांग्रेस में शामिल हो गए। चौधरी चरण सिंह की विरासत अब उनके पौत्र जयंत चौधरी संभाल रहे हैं। वे राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष हैं उन्होंने बाबा चौधरी चरण सिंह व भारत रत्न मिलने पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री का आभास जताते हुए कहा कि आपने 'दिन जीत लिया%'। चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न मिलने के खिलाफ कहीं से कोई आवाज तो नहीं उठ रही है, लेकिन भारत रत्न देने वालाइंग पर जरूर सवाल उठाया जा रहा है। ऐसे चुनाव से पूर्व जब इन बात की चर्चा चल रही है कि चौधरी चरण सिंह के पौत्र जयंत चौधरी व राष्ट्रीय लोकदल के बीजेपी के साथ गठबंधन की चर्चा तेज है, तब इन तरह का फैसला सवाल तो खड़ा करता ही है। चौधरी चरण सिंह विस्यासत में प्रवेश की बात की जाती है तो चरण सिंह सबसे पहले 1937 में छपरौली से उत्तर प्रदेश विधानसभा के लिए चुने गए एवं 1946, 1952, 1962 एवं 1967 में विधानसभा में अपने

आदतन अपराधी भरत उर्फ भानू को हर माह देनी होगी माधवनगर थाना में हाजिरी

द, अचीवर टाइम्स से पृष्ठ
उपाध्याय



मध्य प्रदेश, कटनी। कटनी कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी अविप्रसाद ने आदतन अपराधी भरत उर्फ भानू कुकरेजा के विरुद्ध मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्रवाई करते हुए 6 माह की अवधि तक हर माह एक दिन पुलिस थाना माधवनगर में उपस्थिति दर्ज करने का आदेश पारित किया है। कलेक्टर श्री प्रसाद ने भरत के विरुद्ध यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक कटनी से प्रतिवेदन के आधार पर किया है। अनावेदक भरत उर्फ भानू कुकरेजा पिटा घनश्यम दास कुकरेजा उम्र 27 वर्ष निवासी खेबर लाईन थाना माधवनगर निवासी है और असामाजिक तत्व एवं आदतन अपराधी है। भरत का थाना क्षेत्र में अपराधिक कार्रवाई की गई है परन्तु इसके आचरण में कोई सुधार परिवर्तित करना, हत्या करने की नियत से जानलेवा हमला करना, नहीं हुआ है। अनावेदक की

अधिक मात्रा में शराब कब्जे में रखकर विक्रय करना और लूट करने जैसे अपराधिक मामले विभिन्न न्यायालयों में प्रचलित हैं। भरत के आपराधिक क्षेत्रों और गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिये समय-समय पर प्रतिवधात्मक कार्रवाईयों की गई है परन्तु इसके आचरण में कोई सुधार परिवर्तित करना, हत्या करने की नियत से जानलेवा हमला करना, नहीं हुआ है। अनावेदक की

की सुचना थाने में देने एवं उसके विरुद्ध साक्ष्य देने में भय महसूस करते हैं। इस कारण से भरत अपनी आपराधिक गतिविधियों को लागतार जारी रखा हुआ है। भरत की आपराधिक गतिविधियों के कारण श्वेत में शरीर भाँग एवं लोक प्रशान्ति का खतरा पैदा हो गया है। अनावेदक आम जनता के लिये आतंक का पर्याय बन चुका है। अनावेदक भरत के उपनारीय क्षेत्र माधवनगर कटनी में गौजूद रहने से आम जनों के लिये भय एवं आतंक का वातावरण निर्मित है। इन स्थितियों के महेनजर कलेक्टर श्री प्रसाद ने भरत उर्फ भानू कुकरेजा के विरुद्ध यह एवं म.प्र. राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 3(क) के तहत कार्रवाई करते हुए अनावेदक भरत उर्फ भानू कुकरेजा पिटा घनश्यम दास कुकरेजा उम्र 27 वर्ष निवासी खेबर लाईन थाना माधवनगर निवासी है और असामाजिक तत्व एवं आदतन अपराधी है। भरत का थाना क्षेत्र में अपराधिक उमरन के साथ गाली गलौच, मार्पीट करना, हत्या करने की नियत से जानलेवा हमला करना, नहीं हुआ है। अनावेदक की

अपराधिक गतिविधियों के कारण एवं उसके आपराधिक क्षेत्रों से अपमज्जने का स्वच्छ विचरण करना मुश्किल हो गया है। साथ ही अनावेदक भरत उर्फ भानू कुकरेजा क्षेत्र के आम नागरिक उनके दैनिक जीवन के क्षेत्रों को सामान्य रूप से निवासी खेबर लाईन थाना माधवनगर कटनी के लिये आतंक का पर्याय बन चुका है। अनावेदक भरत के उपनारीय क्षेत्र माधवनगर कटनी में गौजूद रहने से आम जनों के लिये भय एवं आतंक का वातावरण निर्मित है। इन स्थितियों के महेनजर कलेक्टर श्री प्रसाद ने भरत उर्फ भानू कुकरेजा के विरुद्ध यह एवं म.प्र. राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 3(क) के तहत कार्रवाई करते हुए अनावेदक भरत उर्फ भानू कुकरेजा पिटा घनश्यम दास कुकरेजा उम्र 27 वर्ष निवासी खेबर लाईन थाना माधवनगर निवासी है और असामाजिक तत्व एवं आदतन अपराधी है। भरत का थाना क्षेत्र में अपराधिक उमरन के साथ गाली गलौच, मार्पीट करना, हत्या करने की नियत से जानलेवा हमला करना, नहीं हुआ है। अनावेदक की

बूथ कमेटी संगठन की सबसे महत्वपूर्ण इकाई-सीएल वर्मा

द अचीवर टाइम्स दीपक
कर्नौजिया



जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक खीरी की अध्यक्षता में थाना खीरी व कोतवाली सदर में

हुआ थाना समाधान दिवस का आयोजन



द अचीवर टाइम्स एस के सिंह

बहादुर सिंह व पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी, श्री गणेश प्रसाद साहा

द्वारा

लखनऊ विधायक सभा में उपस्थित हरकर-थाना समाधान दिवस का अध्यक्ष थाना खीरी की गई। इस

द्वारा नाम प्राप्त नियायिकायों की सुनवाई

कर विधायक सभा में उपस्थित हरकर-थाना समाधान दिवस का अध्यक्ष थाना खीरी की गई। इस

द्वारा नाम प्राप्त नियायिकायों की सुनवाई

कर विधायक सभा में उपस्थित हरकर-थाना समाधान दिवस का अध्यक्ष थाना खीरी की गई। इस

द्वारा नाम प्राप्त नियायिकायों की सुनवाई

कर विधायक सभा में उपस्थित हरकर-थाना समाधान दिवस का अध्यक्ष थाना खीरी की गई। इस

द्वारा नाम प्राप्त नियायिकायों की सुनवाई

कर विधायक सभा में उपस्थित हरकर-थाना समाधान दिवस का अध्यक्ष थाना खीरी की गई। इस

द्वारा नाम प्राप्त नियायिकायों की सुनवाई

कर विधायक सभा में उपस्थित हरकर-थाना समाधान दिवस का अध्यक्ष थाना खीरी की गई। इस

द्वारा नाम प्राप्त नियायिकायों की सुनवाई

कर विधायक सभा में उपस्थित हरकर-थाना समाधान दिवस का अध्यक्ष थाना खीरी की गई। इस

द्वारा नाम प्राप्त नियायिकायों की सुनवाई

कर विधायक सभा में उपस्थित हरकर-थाना समाधान दिवस का अध्यक्ष थाना खीरी की गई। इस

द्वारा नाम प्राप्त नियायिकायों की सुनवाई

कर विधायक सभा में उपस्थित हरकर-थाना समाधान दिवस का अध्यक्ष थाना खीरी की गई। इस

द्वारा नाम प्राप्त नियायिकायों की सुनवाई

कर विधायक सभा में उपस्थित हरकर-थाना समाधान दिवस का अध्यक्ष थाना खीरी की गई। इस

द्वारा नाम प्राप्त नियायिकायों की सुनवाई

कर विधायक सभा में उपस्थित हरकर-थाना समाधान दिवस का अध्यक्ष थाना खीरी की गई। इस

द्वारा नाम प्राप्त नियायिकायों की सुनवाई

कर विधायक सभा में उपस्थित हरकर-थाना समाधान दिवस का अध्यक्ष थाना खीरी की गई। इस

द्वारा नाम प्राप्त नियायिकायों की सुनवाई

कर विधायक सभा में उपस्थित हरकर-थाना समाधान दिवस का अध्यक्ष थाना खीरी की गई। इस

द्वारा नाम प्राप्त नियायिकायों की सुनवाई

कर विधायक सभा में उपस्थित हरकर-थाना समाधान दिवस का अध्यक्ष थाना खीरी की गई। इस

द्वारा नाम प्राप्त नियायिकायों की सुनवाई

कर विधायक सभा में उपस्थित हरकर-थाना समाधान दिवस का अध्यक्ष थाना खीरी की गई। इस

द्वारा नाम प्राप्त नियायिकायों की सुनवाई

कर विधायक सभा में उपस्थित हरकर-थाना समाधान दिवस का अध्यक्ष थाना खीरी की गई। इस

द्वारा नाम प्राप्त नियायिकायों की सुनवाई

कर विधायक सभा में उपस्थित हरकर-थाना समाधान दिवस का अध्यक्ष थाना खीरी की गई। इस

द्वारा नाम प्राप्त नियायिकायों की सुनवाई

कर विधायक सभा में उपस्थित हरकर-थाना समाधान दिवस का अध्यक्ष थाना खीरी की गई। इस

द्वारा नाम प्राप्त नियायिकायों की सुनवाई

कर विधायक सभा में उपस्थित हरकर-थाना समाधान दिवस का अध्यक्ष थाना खीरी की गई। इस

द्वारा नाम प्राप्त नियायिकायों की सुनवाई

कर विधायक सभा में उपस्थित हरकर-थाना समाधान दिवस का अध्यक्ष थाना खीरी की गई। इस

द्वारा नाम प्राप्त नियायिकायों की सुनवाई

कर विधायक सभा में उपस्थित हरकर-थाना समाधान दिवस का अध्यक्ष थाना खीरी की गई। इस

द्वारा नाम प्राप्त नियायिकायों की सुनवाई

कर विधायक सभा में उपस्थित हरकर-थाना समाधान दिवस का अध्यक्ष थाना खीरी की गई। इस

प्राथमिक विद्यालय असरा के वार्षिक उत्सव पर बच्चों द्वारा सांस्कृतिक प्रोग्राम आयोजित



द अचीवर टाइम्स/चेतन कुमार

एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया और समस्त ग्राम वासियों से आग्रह किया गया की ज्यादा से ज्यादा आयोजन के लिए बच्चों को भवित्वात् आयोजित किया गया एवं उपस्थिति संग्रहीत किया

